

My Notes.....

राष्ट्रीय

सौभाग्य योजना लॉन्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की। इसके तहत 31 मार्च 2019 तक सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने ओएनजीसी के नए कार्पोरेट ऑफिस दीन दयाल ऊर्जा भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए इस योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना के न्यू इंडिया के हर घर में बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल के बाद भी 4 करोड़ घर ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली नहीं है। आज भी इन घरों के लोग, मोमबत्ती, टिबरी और लालटेन से पढ़ते हैं।

क्या है

1. योजना का पूरा नाम - 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' सौभाग्य है।
2. जिनका नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा।
3. जिनका नाम नहीं है वह 500 रुपए देकर बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। ये 500 रुपए आप 10 किस्तों में भी दे सकते हैं।
4. योजना के लिए 16 हजार करोड़ का बजट होगा। योजना के तहत जहां बिजली नहीं पहुंची वहां के घरों को एक सोलर पैक मिलेगा जिसमें 5 एलईडी बल्ब और एक पंखा भी होगा।
5. सौभाग्य योजना का ऐलान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर पंडित दीनदयाल ऊर्जा भवन से किया गया।

सौभाग्य योजना की मुख्य बातें

1. सभी घरों को आसानी से बिजली उपलब्ध होगी
2. मिट्टी के तेल का विकल्प अब बिजली होगी
3. शैक्षिक सेवाओं में सुधार होगा
4. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा
5. संचार के साधन बेहतर होंगे
6. जनता की सुरक्षा में सुधार होगा
7. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
8. जीवन स्तर में सुधार होगा, खासकर महिलाओं को रोज के कामों में सहूलियत मिलेगी

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अम्ब्रेला योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्ब्रेला योजना' को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तीन वर्ष की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है, जिसमें से 18636 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार तथा 6424 करोड़ रुपये राज्यों का अंश है।

क्या है

1. इस योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, किराए पर हेलिकॉप्टर, पुलिस वायरलेस का उन्नयन, राष्ट्रीय सेटलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस परियोजना आदि शामिल हैं।
2. इस अम्ब्रेला योजना में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आंतरिक सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 10132 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश का प्रावधान भी सम्मिलित है।
3. वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 3000 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का प्रावधान किया गया है। इससे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा सुरक्षा तथा विकास गतिविधियों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से वृद्धि होगी।
4. पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनवेस्टीगेशन फेसेलेटीज के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

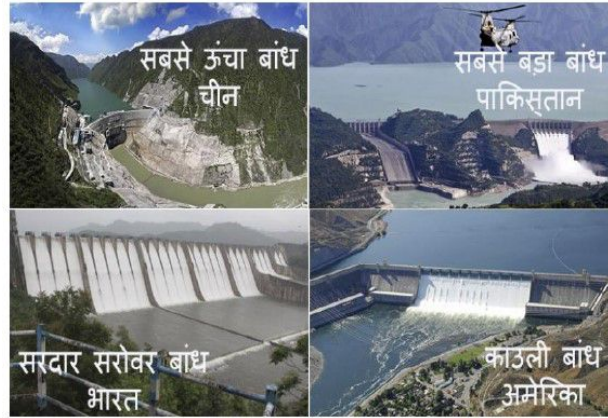
5. इस योजना के कार्यान्वयन से उग्रवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे विभिन्न राज्यों में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सरकार को मदद मिलेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकास में आने वाले अवरोधों से पार पाया जा सकेगा और उसके साथ ही चुनौतियों से प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी।
6. फारेंसिक साइंस लेबोरेटरीज तथा संस्थानों एवं उनमें उपलब्ध उपकरणों सहित पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडिंग हेतु विशेष परियोजना/कार्यक्रमों के लिए भी राज्यों का सहायता के रूप में विशेष नई पहलों की शुरूआत की गई है ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमियों को दूर किया जा सके।
7. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौलिक सुधार लाने के उद्देश्य से पुलिस थानों को आपस में जोड़कर अपराध एवं अपराधियों के रिकॉर्ड का राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करके तथा इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्य स्तम्भों जैसे कारागार, फारेंसिक साइंस लेबोरेटरीज तथा अभियोजन कार्यालय शामिल हैं।
8. इसके अतिरिक्त, इस अम्ब्रेला योजना के तहत अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक नई अत्याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना और जयपुर में सरदार पटेल वैश्विक सुरक्षा केन्द्र का उन्नयन, आतंकवाद निरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि रोकथाम केन्द्र और गांधीनगर, गुजरात में विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान है।
9. 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)' अम्ब्रेला योजना से उनके आधुनिकीकरण द्वारा केन्द्र और राज्य पुलिस बलों की क्षमता और दक्षता में वृद्धि करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

देश को मिला दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को अपने 67वें जन्मदिन पर नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में पिछले कई दशकों से तमाम विवादों में घिरे रहे सरदार सरोवर नर्मदा बांध परियोजना का लोकार्पण और एक रैली को भी संबोधित कर रहे हैं। इस नर्मदा बांध परियोजना की परिकल्पना सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1946 में ही की थी।

सरदार सरोवर नर्मदा बांध परियोजना की खासियत

1. 1945 में सरदार पटेल ने की थी पहल
2. 5 अप्रैल 1961: प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी नींव
3. 56 साल लगे इस बांध को बनाने में
4. 65 हजार करोड़ रुपये हुए खर्च
5. 138 मीटर ऊंचाई, देश में बना सबसे ऊंचा बांध
6. 30 दरवाजे हैं, हर दरवाजे का वजन 450 टन
7. 4.73 मिलियन क्यूबिक पानी जमा करने की क्षमता
8. 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी बांध से
9. 86.20 लाख क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट का प्रयोग बांध बनाने में
10. सरदार सरोवर बांध का सबसे अधिक फायदा गुजरात को मिलेगा। यहां के 15 जिलों के 3137 गांवों के 18.45 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। वहीं, बिजली का सबसे अधिक 57 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलेगा। महाराष्ट्र को 27 प्रतिशत, जबकि गुजरात को 16 प्रतिशत बिजली मिलेगी। दूसरी ओर, राजस्थान को सिर्फ पानी मिलेगा।



‘दीनदयाल हस्तकला संकुल’ राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में ‘दीनदयाल हस्तकला संकुल’ राष्ट्र को समर्पित किया, जो हस्तशिल्प का एक व्यापार सुविधा केंद्र है। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र की आधारशिला नवम्बर, 2014 में रखी थी। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र का दौरा किया और इसे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मंच पर पहुंचने से पहले उन्हें वहां विकसित सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने व्यापार सुविधा केंद्र को लंबे समय तक वाराणसी की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से कारीगरों और बुनकरों को पूरी दुनिया के समक्ष अपने कौशल को पेश करने में मदद मिलेगी और इससे उनका भविष्य उज्वल होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे सभी पर्यटकों को इस केंद्र में आने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि इससे हस्तशिल्प की मांग और बढ़ेगी तथा इसके साथ ही वाराणसी में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, जिससे इस शहर की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से नई गति मिलेगी।

क्या है

1. इस संकुल की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 7 नवम्बर, 2014 को रखी गई थी और प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 22 दिसंबर, 2016 को किया गया था।
2. ‘मुद्रा’ योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण दिये जाते हैं।
3. मुद्रा योजना से 33,000 से भी अधिक बुनकर लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 170 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के ऋण प्राप्त हुए हैं। मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले बुनकर सिर्फ दो माह के भीतर अपनी आमदनी में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि करने में सफल रहे हैं।
4. वित्त मंत्री ने 2014-15 के बजट में वाराणसी के हथकरघों, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने और वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र तथा शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की थी, ताकि घरेलू एवं विदेशी बाजारों में उनकी विपणन गतिविधियों को सुदृढ़ किया जा सके एवं वाराणसी में हथकरघों की समृद्ध परम्परा को आगे बढ़ाया जा सके।
5. व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी के बुनकरों/कारिगरों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकृत करने की दिशा में एक अहम कदम है। व्यापार प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं और कानूनी एवं नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराने हेतु व्यापार सुविधा एवं परामर्श सुविधाएं मुहैया कराना आवश्यक है।
6. यह परियोजना 7.93 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और इसका निर्मित क्षेत्र 43,450 वर्गमीटर है। इस परिसर पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आई है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 30 वीं वर्षगांठ

देश में ओजोन डेप्लेटिंग सबस्टान्स (ओडीएस) को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने का कार्यक्रम सरकार, उद्योगों और अन्य शोयर धारकों के सहयोग के कारण लागू किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डा. हर्षवर्धन ने दी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जागरूकता और सामूहिक कार्य की शक्ति के बल पर इसे हासिल किया जा सकता है। मंत्री महोदय ने इस प्रकारों के अभियानों की सफलता सुनिश्चित करने में बच्चों की भूमिका पर विशेष बल दिया।

क्या है

1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 30 वीं और 23 वें विश्व ओजोन दिवस (16 सितम्बर) पर ‘केयरिंग फॉर ऑल लाईफ अंडर द सन’ थीम पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए डा. हर्षवर्धन ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने पेन इंडिया-जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। यह अभियान हमारी पीढ़ियों में जागरूकता का संचार करेगा।
2. यह कार्यक्रम हमारे विस्तृत कार्यों में रहा जिसे पूरे देश में विभिन्न राज्यों के विद्यालयों व शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की सक्रिय साझेदारी से पूरा किया गया। इस जागरूकता अभियान में 13 हजार से अधिक विद्यालयों के लगभग 28 लाख छात्रों की भागीदारी रही यह देश के 16 राज्यों के 214 जिलों तक पहुंचा।

3. इस अवसर पर डा. हर्षवर्धन ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन के लिए भारत के मजबूत पक्ष को भी रखा। डा. हर्षवर्धन ने कहा कि यह सर्वविदित है कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन को शामिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई है।
4. इस अवसर पर डा. हर्षवर्धन ने प्रकाशन श्रृंखलाओं का विमोचन किया। इनमें न्यू टीआरएसी एसी का पहला संस्करण है। रैफ्रिजिरेशन व एयर कन्डीशनिंग क्षेत्र में सर्विस टेक्नियन से संबंधित न्यूज लेटर- इन दो प्रकाशनों का शुभारम्भ भारत के एच सी एफ सी के प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए किया गया था।
5. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसकी सहयोग एजेंसी है एवं एनर्जी एफिशियन्स सर्विसेस तथा टेरी राष्ट्रीय कार्यान्वयन साझेदार है। इस अवसर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने में भारत की उपलब्धियों के दो वीडियो भी लॉन्च किए गए।

‘अस्त्र’ मिसाइल के परीक्षण पूरे

हवा से हवा में मार कर सकने वाली स्वदेशी विजुअल रेंज ‘अस्त्र’ मिसाइल के विकास संबंधी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। इसके साथ ही इसे वायुसेना में शामिल करने की ओर एक कदम और बढ़ गया है।

क्या है

1. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन परीक्षणों को 11 से 14 सितंबर के बीच ओडिशा समुद्रतट पर स्थित चांदीपुर से बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंजाम दिया गया।
2. एसयू-30 लड़ाकू विमानों के जरिये इन मिसाइलों से पायलट रहित लक्ष्य विमानों (पीटीए) को निशाना बनाया गया।
3. इस दौरान ऐसे सात परीक्षण किए गए और सभी सफल रहे। दो मिसाइलों को युद्धक परिस्थितियों में वारहेड के साथ भी लांच किया गया और उन्होंने लक्ष्यों को बेअसर कर दिया।
4. इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायुसेना ने मिलकर विकसित किया है। जबकि इन्हें लगाने के लिए लड़ाकू विमानों में बदलाव हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किए।
5. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस मिसाइल की तकनीक बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि’ से काफी जटिल है। इसकी वजह यह है कि जब इस मिसाइल को लड़ाकू विमान से लांच किया जाता है तो इसका लक्ष्य दृष्टि में नहीं होता है।

सीबीआइ पूरी तरह से सूचना के अधिकार से बाहर नहीं

भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले की जानकारी साझा करने से सीबीआइ इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि वह सूचना के अधिकार (आरटीआइ एक्ट) से पूरी तरह बाहर है। यह बात दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में जांच एजेंसी ने मुख्य सूचना आयुक्त के उस निर्देश का विरोध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर मामला भ्रष्टाचार का हो तो एजेंसी सूचना के अधिकार से बाहर नहीं है।

क्या है

1. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कहा कि जांच एजेंसी केवल इस आधार पर जानकारी देने से मना नहीं कर सकती कि वह आरटीआइ के सेक्शन 24 के तहत इससे बाहर है।
2. जांच एजेंसी उस स्थिति में ही सूचना देने से इन्कार दे सकती है जब मांगी गई जानकारी सेक्शन 8 (1) के अंतर्गत आती हो।
3. सेक्शन 8 (1) में वह 10 वजह बताई गई हैं जिस आधार पर जांच एजेंसी सूचना देने से इन्कार कर सकती है। इस संबंध में न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें आइबी से आरटीआइ के तहत सूचना मांगी गई थी।
4. बताते चलें की मुख्य सूचना आयुक्त ने एक आरटीआइ कार्यकर्ता की शिकायत पर सीबीआइ को सूचना साझा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही जांच एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया था।

रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में केंद्र सरकार का रुख

रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में रहने को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमान को वापस म्यांमार भेजने को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 16 पनों का हलफनामा सौंपा है। जिसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या इस देश में नहीं रह सकते। अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी।

क्या है वजह

1. **पहली वजह:** केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा सौंप कर जवाब दिया है। जिसमें केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों का देश में रहना गैर कानूनी है। रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल हैं जैसे अपने दूसरे साथियों के लिए फर्जी पेन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराना। कुछ रोहिंग्या मानव तस्करी में भी शामिल हैं।
2. **दूसरी वजह:** देश में करीब 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं ये काफी बड़ी संख्या है। इस वजह से सुरक्षा से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं।
3. **तीसरी वजह:** देश की सुरक्षा की बात कहते हुए केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान आतंकावाद में शामिल हैं। इनके पाकिस्तान और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से भी संपर्क है जो की हमारे देश के लिए खतरा है। इसलिए ये यहां नहीं रह सकते।
4. **चौथी वजह:** देश में जो बौद्ध लोग रह रहे हैं उनके साथ भी हिंसा होने की संभावना हो सकती है।
5. **पांचवी वजह:** केंद्र का कहना है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है।

सरकार का यह जवाब दो रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका पर नोटिस के जवाब में आया है। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने जिरह की थी, जिसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। बता दें कि म्यांमार में हिंसा के कारण पिछले तीन हफ्ते में करीब 380,000 रोहिंग्या लोग भागकर बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। हिंसा की वजह से म्यांमार के रखाइन प्रांत में करीब 30,000 बौद्ध और हिंदू भी विस्थापित हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि म्यांमार की सेना ने आरसा के हमलों की आड़ लेकर करीब 11 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने का अभियान शुरू किया है। म्यांमार की सरकार ने आरोपों से इनकार किया है।

आईएनएस तारासा का जलावतरण

पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट- आईएनएस तारासा का जलावतरण किया। एक भव्य समारोह के दौरान वाइस एडमिरल लूथरा ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अपने कार्यों की बदौलत नए आईएनएस तारासा से पश्चिमी नौसेना कमान और राष्ट्र को ख्याति प्राप्त होगी।

क्या है

1. आईएनएस तारासा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स(जीआरएसई), कोलकाता द्वारा निर्मित वाटर जेट एफएससी का चौथा और अंतिम पोत है।
2. इस श्रेणी के पहले दो पोतों -आईएनएस तारमुगली और तिहायु को 2016 में शामिल किया गया था जो अभी विशाखापत्तनम में स्थित हैं।
3. जबकि आईएनएस तिलाचांग को 9 मार्च 2017 को करवर से नौसेना में शामिल किया गया था।
4. आईएनएस तारासा 50 मीटर लम्बा है और यह तीन वाटरजेट्स से संचालित होता है, जो इसे 35 नोट्स (65 किलोमीटर प्रति घंटा) से अधिक की रफ्तार देते हैं। पोत स्वदेशी तकनीकी से निर्मित 30 एमएम की बंदूकों तथा कई तरह के हल्के, मध्यम और भारी मशीनगनों की क्षमता से लैस हैं।
5. पोत तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की निगरानी, ईईजैड निगरानी के साथ गैर सैन्य अभियानों जैसे-खोज और बचाव, मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों के लिए एक आदर्श मंच है। पोत के कमांडिंग ऑफिसर लैफ्टिनेंट प्रवीन कुमार हैं।

6. यह भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज है, जिसे आईएनएस तारासा का नाम दिया गया है। पहले आईएनएस तारासा ने 1999 से लेकर 2014 तक नौसेना की सेवा की थी।
7. इसे हिन्द महासागरीय क्षेत्र में भारतीय साझेदारी के प्रतीक के रूप में सेशल्स तटरक्षक बल को उपहार में दे दिया गया था। नया आईएनएस तारासा का संचालन मुम्बई स्थिति पश्चिम नौसेना कमान द्वारा किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में संरचना-समझौते की संपुष्टि

फिजी, नाइजर और तुवालु ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन-आईएसए की अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की पांचवीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संरचना समझौते के लिए सत्यापन साधन जमा कराए। इस बैठक में 121 संभावित सदस्य राष्ट्रों, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव श्री आनंद कुमार और सह-अध्यक्षता आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों के राजदूत और फ्रांस सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के क्रियान्वयन हेतु विशेष दूत श्रीमती सिजोलिन रॉयल ने की।

क्या है

1. अब तक 40 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 11 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संरचना समझौते की संपुष्टि की है। 15 देशों की संपुष्टि मिलने के साथ ही आईएसए संधि आधारित अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाएगा।
2. “री-इन्वेस्ट, 2017” के नाम से नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक निवेश सम्मेलन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 7 से 9 दिसंबर 2017 को आयोजित किया जाएगा।
3. इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उपकरण निर्माताओं, तकनीक प्रदाताओं, सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्रीय व राज्य सरकारों, शोध संस्थानों और शैक्षिक जगत जैसे सभी हितधारकों के साथ समझौता करना है। “री-इन्वेस्ट, 2017” नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4. श्री कुमार ने कहा कि आईएसए और सोलर समिति की स्थापना बैठकें “री-इन्वेस्ट, 2017” के साथ ही 8 और 9 दिसंबर, 2017 को आयोजित की जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
5. आईएसए के अंतरिम महानिदेशक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि आईएसए के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन कार्यक्रम लागू किए गए हैं- सामर्थ्य के अनुरूप वित्तीय सहायता, कृषि उपयोग के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग और सौर ऊर्जा के लिए छोटी ग्रिडें।
6. आईएसए सचिवालय की एक पहल है जोखिम कम करने की प्रणाली (सीआरएमएम)। इसके तहत आईएसए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की परियोजनाओं की वित्तीय लागत को कम करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक समूह, प्रणाली के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार कर रहा है जिसे दिसंबर 2018 में लांच किया जाएगा।
7. आईएसए की स्थापना पेरिस घोषणापत्र के तहत हुई है। भारत ने आईएसए कोष के लिए 175 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और आईएसए सचिवालय की लागत को शुरूआती पांच वर्षों में पूरा करने की पेशकश की है।
8. आईएसए एक भारतीय पहल है जिसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में सीओपी -21 के मौके पर किया था।

5G सेवा के लिए बनी समिति

सरकार ने उच्च स्तरीय 5जी समिति गठित की। समिति को 2020 तक प्रौद्योगिकी क्रियान्वित करने के लिये रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, हमने उच्च स्तरीय 5जी कमेटी गठित की है जो 5जी के बारे में दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को लेकर काम करेगी। दुनिया में 2020 में जब 5जी प्रौद्योगिकी लागू होगी, मुझे भरोसा है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा।

क्या है

1. सरकार 5जी से जुड़ी गतिविधियों के लिये 500 करोड़ रुपये का कोष सृजित करने पर काम कर रही है।
2. यह कार्य मुख्य रूप से शोध और उत्पाद विकास का होगा। 5जी प्रौद्योगिकी के तहत सरकार का शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एमबीपीएस की गति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
3. इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल हैं।

असम में एक बड़े कानून को मंजूरी

असम सरकार ने एक बार फिर एक बड़े कानून को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा पास की गई नई जनसंख्या नीति के अनुसार अब दो से ज्यादा बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी सहित किसी भी सरकारी लाभ और सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस कानून में यह प्रावधान भी रखा गया है कि दो से अधिक संतान पैदा करने वाला व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ये फैसला सरकार की उस जनसंख्या नीति का हिस्सा है जिसे एक विस्तृत चर्चा के बाद राज्य विधानसभा के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत सभी राज्य कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए सरकार द्वारा नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

क्या है

1. इसके साथ ही सरकार द्वारा केंद्र के समक्ष ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि दो बच्चों के नियमों का उल्लंघन करने वाले राज्य विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाए और भविष्य में उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जाए।
2. विधानसभा द्वारा पास नई नीति में विवाह के लिए न्यूनतम आयु के नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकेगी।
3. सरकार द्वारा पास किए गए इस कानून में राज्य की जनसंख्या में 17.7 फीसदी की दर से हो रही वृद्धि को विकास की दिशा में एक गतिरोध बताया गया है।
4. गौरतलब है कि साल 2001 की जनसंख्या के अनुसार असम राज्य की जनसंख्या 2.66 करोड़ थी जो कि 2011 की जनगणना के दौरान बढ़कर 3.12 करोड़ दर्ज की गई।

अन्तरराष्ट्रीय

भारत और नार्वे का स्वास्थ्य के लिए आशय पत्र

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नार्वे सरकार के विदेश मामले मंत्रालय के साथ नार्वे-भारत साझीदारी पहल (एनआईटीआई) के जरिये स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर सहयोग बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह सहयोग 2018 से आरम्भ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा। सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) एवं नार्वे के राजदूत महामहिम श्री निल्स रागनार काम्पवाग ने इस आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

क्या है

1. इस पत्र के जरिये भारत और नार्वे के बीच सहयोग भारत सरकार के विकास लक्ष्यों के अनुकूल बना रहेगा, जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए इसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्णित है। यह सहयोग समान हितों के वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
2. इस साझीदारी में प्रजनन, मातृत्व, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं और यह एनआईपीआई चरण-1 और 2 से प्राप्त अनुभवों से और मजबूत होगी। यह सहयोग नवप्रवर्तक, उत्प्रेरक और रणनीतिक समर्थन पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखेगा तथा आरम्भ बिन्दु के रूप में भारत में त्वरित मातृत्व एवं शिशु उत्तरजीविता के लिए भारत सरकार की सघनीकरणीय योजना का उपयोग करेगी।

3. नार्वे और भारत की सरकारों ने 2006 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के आधार पर शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एमडीजी-4 अर्जित करने की दिशा में सहयोग करने पर सहमति जताई थी।
4. यह साझीदारी भारत की स्वास्थ्य पहल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पर आधारित थी और इसका लक्ष्य चार उच्च फोकस राज्यों - बिहार, ओड़िशा, मध्यप्रदेश और राजस्थान में शिशु एवं मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि करना था।
5. चरण-1 (2006-2012) में मुख्य गतिविधियों में, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली के जरिये गृह आधारित नवजात शिशु कल्याण (एचबीएनसी) यशोदा, रुग्ण नवजात स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना (एसएनसीयू), तकनीकी प्रबंधकीय समर्थन एवं टीकाकरण के लिए कार्यनीतिक समर्थन और सार्वजनिक निजी साझीदारी (पीपीपी) पहलों के लिए सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।
6. भारत और नार्वे की सरकारों ने इस साझीदारी को विस्तारित करने का फैसला किया, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (एनएचएम) के दूसरे चरण की पांच वर्षों की अवधि (2013-2017) के अनुरूप है।
7. इन चार राज्यों को एनआईपीआई द्वारा पहले से ही सहायता दी जा रही है और पांचवे राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, जिसमें आरएमएनसीएच + ए गतिविधियों के लिए प्रमुख साझेदार है।

विदेश में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उद्यम

भारत बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। इस परियोजना पर वह रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत-रूस करार के तहत किसी अन्य देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं बनाने के मामले में यह पहला प्रयोग है। यह विदेश में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उद्यम है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष शेखर बसु ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के 61वें सम्मेलन में कहा, 'हम बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर अपने रूसी और बांग्लादेशी साझेदारों के साथ गठबंधन कर रहे हैं।'

क्या है

1. बहरहाल, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत किस तरह का गठबंधन कर रहा है, क्योंकि देश अभी परमाणु हथियार बनाने में उपयोग हो सकने वाली सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करने वाले 48 सदस्यीय समूह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य नहीं है।
2. रूपपुर परियोजना बांग्लादेश की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी। इस परियोजना की दो इकाइयों के चालू होने से भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दक्षिण एशिया का तीसरा देश होगा जो परमाणु विखंडन से ऊर्जा का दोहन करेगा।
3. इसकी हरेक इकाई की क्षमता 1200 मेगावाट की होगी। बसु ने बताया कि भारत सरकार ने देशज तकनीक पर आधारित 10 नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, इन संयंत्रों के साथ हमारे पास निर्माणाधीन 21 और संचालन वाले 22 संयंत्र हो जाएंगे।

जर्मनी की चौथी बार कमान संभालेंगी एंजेला मर्केल

चांसलर एंजेला मर्केल चौथी बार जर्मनी की कमान संभालेंगी। जर्मनी में रविवार को मतदान के बाद आ रहे गैर आधिकारिक परिणामों के मुताबिक मर्केल की पार्टी सीडीयू और सीएसयू गठबंधन को दोहरे अंक की बढ़त है। उनके गठबंधन ने 32-33 फीसदी वोट हासिल किए हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी मार्टिन शुल्ज ने अपनी हार मान ली है।

क्या है

1. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्कल्ज की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) को सबसे खराब हार का सामना करना पड़ा है। उसे सिर्फ 20-21 प्रतिशत वोट ही मिले हैं।
2. इस बीच धुर दक्षिणपंथी पार्टी राष्ट्रपंथी राष्ट्रवादी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) ने संसद में अपनी पहली सीट हासिल की है। चुनाव सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मर्केल की कंजरवेटिव सीडीयू और सीएसयू गठजोड़ को एसपीडी पर दोहरे अंकों में बढ़त हासिल है।

3. जर्मनी की संसद के निचले सदन 'बुंदेसटैग' में प्रवेश के लिए चार पार्टियों के पांच फीसदी की सीमा पार करने का अनुमान है। ऐसे में अगली सरकार के गठन में महीनों लग सकते हैं।
4. शरणार्थियों का विरोध करने वाली एएफडी जर्मनी की तीसरी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभर सकती है।
5. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से पहली बार 'बूनदशताग' में असली नाजियों के प्रवेश से सतर्क नेताओं ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे दक्षिणपंथी एएफडी को खारिज कर दें।

वर्ल्ड के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप पर डाक टिकट जारी

चीन ने 18 सितम्बर 2017 को गुइज़ोऊ प्रांत में स्थित वर्ल्ड के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के प्रतीक स्वरूप टिकट जारी किया है। स्टेट पोस्ट ब्यूरो (एसपीबी) ने पांच टिकट का एक सेट जारी किया है, जिसमें एक टिकट पर पांच सौ मीटर लंबे अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप को चिह्नित किया गया है। इस एक टिकट की कीमत 1.2 युआन है क्या है

1. अन्य चार टिकटों में से एक को चीन के क्वांटम विज्ञान प्रायोगिक उपग्रह मोजी, दूसरे को शोध पोत तानसोऊ-1 और तीसरे को सनवे ताइहूलाइट सुपरकंप्यूटर के सम्मान में जारी किया गया है।
2. 1.2 अरब युआन के निवेश वाले विशालकाय दूरबीन का व्यास लगभग आधा किलोमीटर तक है।
3. दूरबीन को अंतरिक्ष पर जीवन के संकेतों की जांच करने के लिए बनाया गया है और यह किसी भी विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील है।

UNHRC में भारत का बयान

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का चेहरा बताया है। भारत ने इस्लामाबाद से देश में आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद करने और टेररिस्ट्स को सजा दिलवाने के लिए कहा है।

क्या है

1. परिषद के 36वें सत्र में पाकिस्तान के बयान का जवाब देते हुए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विष्णु रेड्डी ने कहा, 'पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन उनके देश की धरती से संचालित हो रहे हैं। पाकिस्तान को इन आतंकी फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए और गुनहगारों को सजा दिलाना चाहिए।'
2. भारत ने जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों को मिल रहे समर्थन के पक्के सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। विष्णु रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग बताया।
3. उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसे मसलों पर जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वह बेतुके बयान देकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मुद्दे से ध्यान भटक रहा है। पाकिस्तान को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

भारत, अमेरिका और जापान के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक

भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बैठक में समुद्री सुरक्षा, संपर्क और प्रसार के मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि मंत्रियों ने नैविगेशन की आजादी, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया, 'समुद्री सुरक्षा संपर्क और प्रसार के मुद्दों पर भारत, अमेरिका और जापान के बीच यह तीसरी त्रिपक्षीय बैठक है।'

क्या है

1. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पांच देशों- ट्यूनिशिया, लातविया, दुबई, डेनमार्क और बहरीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। उन्होंने भूटान और बांग्लादेश के प्रमुखों को भी बुलाया।

2. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने जानकारी दी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इवांका ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में आयोजित ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट (जीईएस) में शामिल होने आ रही इवांका से कई मुद्दों पर बात की। इसमें महिला सशक्तिकरण का मुद्दा प्रमुख था।
3. कुमार ने बताया कि स्वराज दुबई के विदेश मंत्री से मिलीं और भारत में विदेशी निवेश पर चर्चा की। उन्होंने आगे बताया कि बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात में स्वराज ने क्षेत्रीय मुद्दों विशेषकर खाड़ी के हालात पर चर्चा की।
4. सात दिनों के लिए न्यूयार्क पहुंची सुषमा स्वराज संरा महासभा के साथ कई बैठकों में शामिल होंगी। इसमें से पहली बैठक अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिल्लरसन के साथ है। 23 सितंबर को संरा महासभा में संबोधन के साथ सुषमा स्वराज कई अन्य द्विपक्षीय बैठक और बहुपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगी।

संयुक्त राष्ट्र लीडरशिप समिट ऑन इनवॉयरमेंट पैक्ट

भारत ने ऐतिहासिक पैरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए समझौते से आगे और उससे कहीं ज्यादा काम करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र लीडरशिप समिट ऑन इनवॉयरमेंट पैक्ट के दौरान कहा कि भारत पर्यावरण और विकास पर चर्चा में सबसे आगे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जून में पैरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की थी जिसके बाद इस समझौते में अमेरिका की भूमिका पर अनिश्चितता के बीच सुषमा की यह टिप्पणी आई है। अमेरिका ने दलील दी थी कि इस समझौते में भारत और चीन जैसे देशों को अनुचित लाभ मिल रहा है। दुनिया में कार्बन उत्सर्जित करने वाले तीसरे सबसे बड़े देश भारत ने दिसंबर 2015 में 190 से अधिक देशों के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसका लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को रोकना और इसे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना है।

क्या है

1. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस की मेजबानी वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए स्वराज ने कहा कि भारत पैरिस समझौते से आगे और उससे कहीं ज्यादा काम करने का इच्छुक है।
2. भारत और फ्रांस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर मिलकर काम कर रहे हैं। दिन में सुषमा ने मेक्सिको, नॉर्वे और बेल्जियम के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की जिसमें मुख्य ध्यान द्विपक्षीय संबंधों पर रहा। बेल्जियम की ओर से इस वर्ष भारत की उच्च स्तरीय यात्रा की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। सुषमा का सान मारिनो, ब्राजील, मोरक्को, मॉल्डोवा के अपने समकक्षों और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। उनका जी-4 (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) और शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक समेत कई बैठकों में भाग लेने का भी कार्यक्रम है।

अर्थशास्त्र

भारत के पहले स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज

द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) अगले 12 से 18 महीने के भीतर भारत के पहले स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना करने में मदद करने के लिए जल्द ही एक समिति बनाने की योजना बना रहा है। उद्योग संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। फिजिकल गोल्ड के लिए एक डेडिकेटेड एक्सचेंज होने से उस बाजार में पारदर्शिता लाने के अलावा जहां बड़े लेन देन की संभावनाएं हैं, भारत में सोने के मानक मूल्य निर्धारण की शुरुआत होगी। डब्ल्यूजीसी में भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम पीआर ने बताया, "हम समिति के गठन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें सभी हितधारक (स्टेकहोल्डर्स) शामिल होंगे।"

क्या है

1. देश में एक स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज की जरूरत पर प्रकाश डालने वाली डब्ल्यूजीसी रिपोर्ट को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि समिति जिसके दिसंबर तिमाही में गठित होने की संभावना है, वो एक्सचेंज का गठन नहीं करेगी, बल्कि वह इसकी स्थापना में एक मार्गदर्शक का काम करेगी।

2. साल 2015 में ही भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय गोल्ड एक्सचेंज का प्रस्ताव सामने रखा था। भारत में इस तरह के एक्सचेंज की जरूरत पर जोर बीते साल गोल्ड मोनेटाइजेशन और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी करने के बाद दिया गया है।
3. इनका प्रमुख उद्देश्य देश के सोने के भंडार को एक जगह एकत्रित करना था। ऐसा इसलिए ताकि देश में सोने के आयात को कम किया जा सके, जो कि व्यापार घाटे पर असर डालता है।
4. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) वर्तमान में भारत में सोने के वायदा अनुबंध को पेश करते हैं, लेकिन गोल्ड के फिजिकल ट्रेड के लिए अब तक कोई मंच नहीं है।

कारोबारी रैंकिंग में भारत का स्थान

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग एक पायदान गिरकर 40वीं है। सबसे प्रतिस्पर्धी देशों की इस सूची में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। डब्ल्यूईएफ की 137 देशों की सूची में अमेरिका दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा। इस सूची में भारत 39वें स्थान से एक पायदान खिसककर 40वें पर पहुंच गया। इस सूची में चीन की रैंकिंग 27वीं रही। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो साल में अच्छी छलांग लगाने के बाद भारत की रैंकिंग कमोबेश स्थिर रही। हालांकि प्रतिस्पर्धा के ज्यादातर मानकों में भारत ने सुधार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 66वें, उच्च शिक्षा में 75वें और टेक्नोलॉजीकल रेडीनेस में 107वें स्थान पर रहा। इससे लगता है कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ा है।

क्या है

1. डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग आइसीटी यानी इन्फोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खासकर प्रति यूजर इंटरनेट बैंडविथ, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन और स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता के मामले में बेहतर हुई है।
2. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र भारत में कारोबार के लिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या मानता है। भारत के लिए बड़ी चिंता इस बात की है कि इनोवेटिव स्ट्रैथ और उसकी टेक्नोलॉजीकल रेडीनेस (तीन पायदान के सुधार के साथ 107वां स्थान) के बीच संबंध नहीं बन पाया है। इस अंतराल के कारण भारत अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए अपनी तकनीकी ताकत का लाभ नहीं उठा पाएगा।
3. सूची में ब्रिक्स देशों में चीन और रूस भारत से ऊपर हैं। रूस की रैंकिंग 38वीं रही है। दक्षिण अफ्रीका 61वें और ब्राजील 80वें स्थान पर रहा। हालांकि दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों में भारत सबसे आगे रहा।
4. भूटान 82वें, श्रीलंका 85वें, नेपाल 88वें, बांग्लादेश 99वें और पाकिस्तान 115वें स्थान पर रहे। डब्ल्यूईएफ के अनुसार दक्षिण एशिया में पिछले एक दशक के दौरान टेक्नोलॉजीकल रेडीनेस में कोई सुधार नहीं हुआ। अब आइसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है। हालांकि इसका उपयोग अभी भी चुनौती है। ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स प्रतिस्पर्धा के 12 मानकों को आधार बनाकर तैयार किया गया है।
5. इंस्टीट्यूटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रोइकोनॉमिक हालात, स्वास्थ्य व प्राइमरी शिक्षा, उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण, मार्केट एफीशिएंसी, लेबर मार्केट एफीशिएंसी, वित्तीय बाजार विकास, टेक्नोलॉजीकल रेडीनेस, बाजार का आकार, कारोबारी जटिलता और इनोवेशन को रैंकिंग के लिए आधार बनाया गया है।
6. डब्ल्यूईएफ के इस साल के सर्वे के अनुसार भारत में कारोबार के लिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या मानी गई है। इसके बाद की दिक्कतों में वित्त पोषण, टैक्स रेट, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, श्रम शक्ति में नैतिकता का अभाव और अपर्याप्त शिक्षित श्रम शक्ति हैं।

ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2017

भारत ने खुदरा क्षेत्र के लिए विश्व के पसंदीदा ठिकानों के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। इंडिया रिटेल फोरम-2017 में एटी कार्ने के पार्टनर शुभेंदु रॉय ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरी है। इसके पीछे उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी, मोबाइल व इंटरनेट के बढ़ते प्रसार, विदेशी निवेश के लिए

अनुकूल माहौल और कैशलेस लेनदेन व जीएसटी पर सशक्त फ़ैसलों की अहम भूमिका रही है। शुभेंदु रॉय ने कहा कि इन कदमों से भारत में पारदर्शिता और सुगमता से ग्लोबल ब्रांडों का प्रवेश हुआ।

क्या है

1. इस साल की इंडिया रिटेल रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12-15 महीनों में भारत में 100 फीसद कैश एंड कैरी के कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में भारत में कदम रखने वाली थाइलैंड की सियाम मैक्रो नवीनतम कंपनी है। इससे पहले मेट्रो, वॉलमार्ट और बुकर भारतीय बाजार में आकर इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
2. स्वीडन की फर्नीचर निर्माता आइकिया ने 2017 के अंत तक देश में अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेयरहाउस खोलने की बात कही है। यह सेंटर पुणे में होगा। 2018 में कंपनी हैदराबाद में अपना स्टोर भी खोलेगी। 1.56 अरब डॉलर (करीब 100 अरब डॉलर) के निवेश से कंपनी भारत में 25 स्टोर खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
3. बड़े रिटेलर और ब्रांडों के साथ-साथ दुनियाभर के मिड सेगमेंट ब्रांड भी भारत में रिटेल कारोबार की सुगम नीतियों का लाभ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। फूड रिटेल ब्रांड जैसे कि कोरेस, मिगाटो, इविसु, वॉलस्ट्रीट इंग्लिश, पास्ता मेनिया, लश एडिक्शन, मेल्लिंग पॉट, योगर्ट लैब और मोनालिसा समेत दुनियाभर के कई अन्य ब्रांड भारत में 30 से 50 करोड़ डॉलर (1,930-3,215 करोड़ रुपये) तक का निवेश करने की तैयारी में हैं।
4. भारतीय खुदरा बाजार यानी रिटेल मार्केट में ग्लोबल भागीदारी बढ़ने से यह सेक्टर तेजी से विकास करेगा। इससे यह और ज्यादा संगठित होकर सामने आएगा।

सेबी चीफ दुनिया के टॉप 10 नियामकों में शामिल

बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को दुनिया के टॉप 10 नियामकों में शामिल किया गया है। यह बात एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। त्यागी को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन पद पर इस वर्ष मार्च में नियुक्त किया गया था। टॉप 10 की सूची में त्यागी 7वें पायदान पर हैं।

क्या है

1. यह रैंकिंग बिजनेस स्ट्रक्चर में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों का हिस्सा है। इसे द एक्सचेंज इन्वेस्ट 1000 (ईआई1000) भी कहा जाता है। इसे पैट्रिक यंग एंड एक्सचेंज इन्वेस्ट ने लॉन्च किया था।
2. अमेरिका की ट्रेडर्स मैगजीन ऑनलाइन ने एक रिपोर्ट में बताया कि एक विशेष पद्धति को अपनाते हुए ईआई1000 इंडेक्स व्यक्तिगत तौर पर लोगों को सेक्टर पर उनकी ओर से पड़े प्रभाव के स्तर पर रैंकिंग देता है।
3. टॉप 10 नियामकों की सूची में यूरोपीय संघ के कमिश्नर (प्रतिस्पर्धा) मार्ग्रेथे वेस्तेगर को पहला स्थान मिला है। दूसरे पायदान पर ईएसएमए चेयरमैन स्टीवन मैजूर को जगह मिली है।
4. वहीं अजय त्यागी को इस सूची में सातवां स्थान मिला है। लिस्ट को तैयार करने में कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया जिसमें, प्रभावशाली शख्स का पदभार, कार्यप्रणाली, इंडस्ट्री में उसकी भागेदारी शामिल रहा।
5. सूची में अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनियम आयोग के चेयरमैन जे क्लेटन (तीसरे), कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के चेयरमैन जे क्रिस्टोफर ज्ञानकार्लो चौथे, चाइन सिक््योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन शियू ल्यू पांचवें और फाइनेंशियल कंडक्ट अथारिटी यूके के सीईओ एंड्रयू बेली छठवें स्थान पर रहे।

टाटा संस को प्राइवेट लिमिटेड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी

करीब 6.82 लाख करोड़ रुपये कारोबार वाले टाटा समूह की प्रमोटर कंपनी टाटा संस को प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बदलने के प्रस्ताव को शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई। इससे साइरस मिस्त्री के परिवार द्वारा अपनी हिस्सेदारी किसी बाहरी को बेचने की संभावनाएं सीमित होंगी। टाटा संस से जुड़े सूत्र ने बताया कि शेयरधारकों की सालाना आम बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पारित हो गए। सालाना आम बैठक में कंपनी के रजिस्ट्रेशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी से बदलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।

क्या है

1. मिस्त्री परिवार ने इस पहल को छोटे शेयरधारकों के खिलाफ बताते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान की बात कही थी। **मिस्त्री परिवार की टाटा संस में 18.4 फीसद हिस्सेदारी है।**
2. टाटा के ट्रस्टों की हिस्सेदारी 66 फीसद है। अभी यह पता नहीं चला है कि कितने फीसद शेयरधारकों ने पक्ष में और कितने लोगों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 75 फीसद शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरत है।
3. मिस्त्री को हटाने के बाद जनवरी में एन. चंद्रशेखरन को टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरधारक किसी को भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरधारक बाहरी निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकते। पिछले हफ्ते कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि यह कदम कंपनी के हित में उठाया जा रहा है।
4. **नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री की दो कंपनियों की अपील को स्वीकार कर लिया है।** कंपनियों ने टाटा संस के खिलाफ उत्पीड़न एवं कुप्रबंधन का मामला दायर करने के लिए शेयरधारिता के नियमों में छूट मांगी थी। नियमानुसार ऐसा मामला दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के पास संबद्ध कंपनी में कम से कम 10 फीसद शेयर होना चाहिए।

LTCG मामला

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन 14 कंपनियों पर से ट्रेडिंग बैन हटा दिया है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। नियामक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इन कंपनियों के खिलाफ इस संबंध में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं।

क्या है

1. **सेबी का ताजा फैसला:** सेबी के 22 सितंबर के ताजा आदेश में कहा गया है कि इन 14 इकाइयों के खिलाफ किसी तरह का प्रतिकूल प्रमाण नहीं मिला। इसलिए इनसे प्रतिबंध हटाया जा रहा है। शेष 17 इकाइयों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
2. नियामक का यह अहम फैसला **कमलाक्षी फाइनेंस कारपोरेशन (केएफसीएल) के संदर्भ में सामने आया है।** इन सभी कंपनियों को अनुचित लाभ के लिए कंपनी के शेयरों मूल्यों को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का जिम्मेदार माना गया था।
3. इसी महीने नियामक ने अभी तक धोखाधड़ी वाले तरीके से दीर्घावधि का लाभ कमाने (एलटीसीजी) के विभिन्न मामलों में कुल 750 इकाइयों से बैन हटाया है।
4. **केएफसीएल, जिसे अब ग्रोमो ट्रेड एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, से जुड़े ताजा मामले में** सेबी ने फरवरी 2015 में 33 इकाइयों को स्टॉक मार्केट में कारोबार करने से प्रतिबंधित किया था। नियामक ने जनवरी से दिसंबर, 2014 के दौरान केएफसीएल के शेयरों के मूल्यों की समीक्षा की थी।

ओईसीडी के अंतरिम आर्थिक आउटलुक

भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष में 6.7 फीसद की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ने का अनुमान है। ऐसा नोटबंदी और जीएसटी कार्यान्वयन के कारण आए क्षणभंगुर प्रभाव के चलते है। **पेरिस के एक थिंक टैंक कहे जाने वाले ओईसीडी का कुछ ऐसा ही मानना है।** आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने इसके अलावा अगले वित्त वर्ष (2018-19) के अनुमान को भी कम कर 7.2 फीसद कर दिया है। इस अवधि के लिए जून में जीडीपी का विस्तार 7.7 फीसद पर आंका गया था।

क्या है

1. **ओईसीडी के अंतरिम आर्थिक आउटलुक के अनुसार साल 2017-18 में, भारत की विकास दर के जून के (7.3 फीसद) मुकाबले 6.7 फीसद रहने का अनुमान है।** यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में, “नोटबंदी के प्रभाव और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के क्षणभंगुर प्रभाव ने साल 2017 के ग्रोथ अनुमान को कम करने पर जोर दिया है।”

2. लंबी अवधि में जीएसटी के कारण निवेश, उत्पादकता और विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर को पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जबकि नोटबंदी को 8 नवंबर 2016 में लागू किया गया जिसने 500 और 1000 रूपए के नोटों को अमान्य कर दिया था।
3. वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में ओईसीडी ने कहा कि इस वर्ष विकास दर के 3.5 फीसद और साल 2018 में 3.7 फीसद तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं मौद्रिक नीति के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मुद्रास्फीति 4 फीसदी से कम या आसपास रहती है भारत में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश है।

लागू हुए सख्त नियम

कॉरपोरेट घराने सिर्फ दो स्तर की ही सहयोगी कंपनियां यानी सब्सिडियरी रख सकेंगे। सरकार ने इसके लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। जिन कंपनियों ने पहले ही सब्सिडियरी के दो से ज्यादा स्तर बना रखे हैं, उन्हें इनके बारे में सरकार को ब्योरा देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। अगर उल्लंघन बार-बार किए जाते हैं तो रोजाना 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। सरकार ने यह कदम अवैध धन की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। इन बंदिशों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ ही बीमा फर्मों और सरकारी कंपनियों को मुक्त रखा गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इन नियमों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही ये नियम 20 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं। अवैध धन को इधर से उधर करने के लिए लोग धड़ाधड़ कंपनियां बना रहे थे। कई स्तरों वाली सहयोगी कंपनियों का मकड़जाल बनाने से धन की हेराफेरी आसान हो जाती है।

क्या है

1. बाजार नियामक सेबी ने कर चोरी के लिए शेर बाजार का दुरुपयोग करने के मामले में प्रतिबंध झेल रही कंपनियों में से 244 फर्मों को राहत दे दी है।
2. नियामक ने इनके खिलाफ जांच में कर चोरी का कोई सबूत नहीं पाया। इसके बाद ही नियामक ने इन यूनियों पर लगे कारोबार के प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है।
3. इसी महीने सेबी ने चार अलग मामलों में 500 यूनियों से पाबंदी हटाई थी। नियामक ने इसी मामले में तीन और कंपनियों के खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला किया है।

विज्ञान एवं तकनीकी

धरती पर 3.5 लाख वर्ष पहले आए थे मानव

पृथ्वी पर मानव की वर्तमान प्रजाति 3.5 लाख वर्ष पूर्व आई थी। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2300 से 300 वर्ष के बीच दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले सात लोगों के जीनोम (जीवों के जीन का समूह) का अध्ययन किया। शोध में मिली जानकारियों के अनुसार मानव प्रजाति के विकास के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र का अहम योगदान रहा है।

क्या है

1. 2300 से 1800 वर्ष पूर्व रहने वाले तीन व्यक्तियों के जीनोम से पता चला कि वे खोए-सान ग्रुप (अफ्रीका में रहने वाली मानव की जाति) के वंशज हैं।
2. वहीं 500-300 वर्ष पूर्व रहने वाले चार लोगों के जीनोम अभी दक्षिण अफ्रीका में बांटू बोलने वाली जाति से संबंधित मिले।
3. शोधकर्ताओं ने पाषाण काल के शिकारी मनुष्यों के जीनोम का अध्ययन कर पता लगाया कि मानव में सबसे बड़ा बदलाव 3.5 और 2.6 लाख वर्ष के बीच आया।
4. दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर रहने वाले पाषाण काल के शिकारी बच्चे और पश्चिम अफ्रीका के मानडिंका के बीच तुलनात्मक अध्ययन के बाद मालूम हुआ कि मानव प्रजाति में सबसे बड़ा विभाजन 3.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था।

5. इन शोध के परिणाम के अनुसार मनुष्य की आधुनिक प्रजाति हमारे अनुमान से बहुत पहले ही विकसित हो गई थी।

गर्मी और सूखे में कैसे बचती है यह फसल

वैज्ञानिकों के एक समूह ने यह पता लगाने में सफलता हासिल की है कि बाजरा किस तरह अत्यधिक गर्मी और सूखे में खुद को बचा पाने में सफल रहता है। इसके लिए 30 शोध संस्थानों में 65 वैज्ञानिकों ने बाजरे के जीनोम को डीकोड किया। उनका दावा है कि इस शोध से मौजूदा वैश्विक जलवायु परिवर्तन और खाद्य संकट के इस दौर में अन्य अनाज के उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।

क्या है

1. शोधकर्ताओं का कहना है कि वातावरण में बढ़ते तापमान और गर्म तरंगों की बढ़ती संख्या के कारण प्रमुख फसलों के उत्पादन में कमी आना तय है। ऐसे में यह शोध इस कमी को रोकने में मदद करेगा।
2. वैज्ञानिकों ने जीनोम को डीकोड करने के बाद भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों को भी तैयार किया है। गौरतलब है कि बाजरे का उत्पादन 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले इलाकों में भी होता है। इस शोध का प्रकाशन नेचर बायोटेक्नोलॉजी जर्नल में किया गया है।
3. शोध में तेलंगाना स्थित इंटरनेशनल क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट फार सेमी आर्बिड ट्रापिक्स, चीन के बीजीआइ शेनजेन और फ्रांस के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विशेष योगदान रहा।
4. शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने उन आणविक मार्कर की पहचान की जो सूखे और गर्मी को सह पाने की क्षमता से संबंधित थे। इन आनुवंशिक टूल की मदद से अन्य फसलों को भी गर्मी सहने के योग्य बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
5. शोधकर्ताओं का यह भी कहना था कि इन मार्कर की सहायता से अफ्रीका और एशिया के शुष्क और अर्द्ध शुष्क इलाकों में बाजरे का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जैव प्रौद्योगिकी नई ऊंचाई पर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन के लिए कई कदम उठाए हैं। समावेशी विकास के संदर्भ में डीबीटी ने कई कार्यक्रमों और मिशनों की घोषणा की है। डीबीटी ने 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम मैनेजमेंट सेल (एनईआर-बीपीएमसी)' का गठन किया है। इसका वार्षिक निवेश 180 करोड़ रुपये है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी शोध को गति प्रदान करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर केन्द्रीय विज्ञान और तकनीकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख पहलों की घोषणा की। ये पहलें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के दर्शन के अनुरूप हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि डीबीटी ने यह फैसला लिया है कि वह प्रत्येक वर्ष अपने बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र को समर्पित करेगा।

क्या है

1. **फाइटो-फार्मा प्लान्ट मिशन** :- यह 50 करोड़ रुपये का मिशन है जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय और लुप्त होने के खतरे को झेल रहे औषधीय पौधों का संरक्षण है।
2. **ब्रह्मपुत्र जैव विविधता और जीवविज्ञान बोट (बी 4)** :- यह एक प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटकों के विश्लेषण के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला है। बी 4 में मिट्टी, पानी, पर्यावरण, पौधे व पशु जीवन, मानव स्वास्थ्य और कृषि घटक का विश्लेषण करने की क्षमता होगी।
3. **फोल्डस्कोप के माध्यम से फ्रूगल माइक्रोस्कोपी**:- कागज का एक पन्ना और लेंस जैसे सरल घटकों से बना एक माइक्रोस्कोप देश के बाकी हिस्सों के साथ, क्षेत्र से छात्रों और विज्ञान को जोड़ना एक उपकरण के रूप में काम कर रहा है जो क्षेत्र से छात्रों और विज्ञान को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ रहा है। विद्यालयों व कॉलेजों से कुल 525 आवेदन प्राप्त हुए हैं: विद्यालयों से 112, कॉलेजों से 357 और नागरिक वैज्ञानिकों से 56। सभी आवेदकों को 4 लाख से 8 लाख के बीच सूक्ष्म अनुदान प्रदान किया जाएगा

4. **ट्विनिंग आर एंड डी कार्यक्रम:** डीबीटी ने 480 आर एंड डी कार्यक्रमों की शुरुआत की है जो देश भर के संस्थानों से जुड़े हैं। इसके लिए पिछले तीन वर्षों में 90 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप 252 शोधों का प्रकाशन हुआ और 600 जूनियर और वरिष्ठ छात्रों को अनुसंधान फेलोशिप दी गई। 40 करोड़ की लागत से डीबीटी ने 11 मेडिकल कॉलेजों में जांच सुविधाओं की व्यवस्था की है।

विविध

पी.वी सिंधु ने रचा इतिहास

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कोरिया ओपन में जापान की ओकुहारा को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 22-20, 11-21, 21-18 से हराकर कोरिया ओपन सुपर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। ओलंपिक में सिल्वर जीत चुकी पी वी सिंधु का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नोजोमी ओकुहारा को एक घंटे 24 मिनट तक चले मुकाबले में करारी मात दी। इसके साथ ही सिंधु ने एक बार इतिहास रच कर, ओकुहारा से पिछले महीने का बदला ले लिया। बता दें कि पिछले महीने हुए वर्ल्ड चौंपियनशिप के फाइनल में ओकुहारा ने सिंधु को हराकर चौंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी।

क्या है

1. सिंधु का मुकाबला सेमीफाइनल में चीन की बिंजिआओ को 21-10, 17-21, 21-16 से हराया। इस मुकाबले में सिंधु की जबर्दस्त शुरुआत रही थी। उन्होंने पहला गे 16 मिनट में ही जीत लिया।
2. हालांकि दूसरे गेम में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर तीसरे गेम में वापसी करते हुए चीनी शटलर को हराया।

इस बीमारी की वजह से हुई सबसे ज्यादा मौतें

दिल की बीमारी आज भी इंडिया में हो रही मौतों की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2016 में कुल 17 लाख लोगों की मौत सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से हुई है। यह आंकड़ा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2016 में इसका खुलासा हुआ है। यह आंकड़ा 15 सितंबर 2017 को जारी किया गया।

क्या है

1. आंकड़े में अन्य कई बातों का भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल होने वाली मौतों में से 17% से ज्यादा मौतें सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से हुई है।
2. यह आंकड़ा 2005 की तुलना में 53% तक ज्यादा है।
3. 2005 से 2016 के बीच डायरिया से होने वाली मौतों में 26% की गिरावट आई है।
4. धमनियों में होने वाली बीमारी 2016 में होने वाले मौतों की चौथी सबसे बड़ी वजह है। 2005 के मुकाबले इसमें 25% का इजाफा हुआ है। यह बीमारी कुल 694000 मौतों की जिम्मेवार रही।
5. टीबी की बीमारी देशभर में हो रहे मौतों की छठी सबसे बड़ी वजह है। इससे कुल 4,35,000 लोगों की मौत हुई। अच्छी बात ये है कि 2005 की तुलना में इस बीमारी से होने वाली मौतों में गिरावट आई है।
6. इसके अलावा सड़क दुर्घटना देशभर में हो रही मौतों की आठवीं सबसे बड़ी वजह है। 2005 की तुलना में 2016 में सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों में 22% का उछाल आया है। 2016 में कुल 2,54,000 मौतें हुई हैं।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 के 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। जेएनपीटी को यह पुरस्कार स्वायत्त संस्थाओं व परिषदों के लिए निर्धारित बी-श्रेणी के अंतर्गत दिया गया।

क्या है

1. 14 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के दौरान यह पुरस्कार (द्वितीय पुरस्कार) प्रदान किया गया।

- जेएनपीटी के उपाध्यक्ष श्री नीरज बंसल ने महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4

कुपोषण के कारण देश में करीब 38 फीसदी बच्चों का कद नहीं बढ़ पा रहा है। इनमें से भी करीब 21 फीसदी बच्चों में यह समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4' में यह तथ्य सामने आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुपोषण की समस्या इतनी गंभीर है कि वह भावी नस्ल को प्रभावित कर सकती है।

क्या है

- यह सर्वेक्षण 2015-16 के दौरान देश भर में हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पांच साल की उम्र के 38.5 फीसदी बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम थी। छोटे कद वाले बच्चों की संख्या शहरों में 31 फीसदी और गांवों में 41 फीसदी है।
- इसके मद्देनजर एक अलग श्रेणी बनाई गई, जिसमें कद छोटा होने से अत्यधिक प्रभावित बच्चों को रखा गया है। ऐसे बच्चों की संख्या 21 फीसदी है। ऐसे बच्चों का गांवों एवं शहरों में प्रतिशत करीब-करीब एक जैसा ही है।
- चिकित्सकीय मानकों के अनुरूप पांच साल के बच्चे का कद 40 इंच होना चाहिए। उम्र के हिसाब से कितना कद होना चाहिए इसके लिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से चार्ट उपलब्ध है, जिसके आधार पर आकलन किया जाता है। इसमें जन्म के समय के बच्चे के कद को भी आधार बनाया जाता है।
- दिल्ली स्थित वर्धमान महावीर कॉलेज के प्रोफेसर जुगल किशोर के अनुसार ऐसे बच्चों की जब उम्र बढ़ती है और उनका खानपान बेहतर होता है तो वे जल्दी मोटापे की चपेट में आ जाते हैं। यदि वे कुपोषण से मुक्त नहीं हो पाते तो उन्हें बीमारियों का खतरा ज्यादा हो सकता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय में उप आयुक्त डॉ. अजय खेड़ा के अनुसार बचपन में यदि कद छोटा रहता है और आगे भी उनकी सेहत नहीं सुधरती है। ऐसे बच्चों के जब बच्चे होंगे तो आनुवांशिक प्रभाव से उनका कद भी छोटा हो सकता है। उनका कहना है कि पहले यह स्थिति ज्यादा गंभीर थी।
- जापान एवं चीन के बच्चों के कद में सुधार हो रहा है। वहां छोटे कद के बच्चों की संख्या तीन-चार फीसदी के बीच होती है। पोषण अच्छा होने से इनकी नस्लें सुधर रही हैं।

वर्ल्ड टॉप 100 लिविंग बिजनेस माइंड्स सूची

दुनिया में सबसे अच्छा कारोबारी दिमाग रखने वाले जीवित दिग्गजों (लिविंग लीजेंड्स) की शीर्ष 100 की सूची में लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा और विनोद खोसला जैसे तीन भारतीय शामिल हैं। इस विशेष सूची को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के 100 महान जीवित कारोबारी मस्तिष्क शीर्षक से तैयार किया है। लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। रतन टाटा, टाटा समूह के मानद चेयरमैन हैं और विनोद खोसला सन माइक्रोसिस्टम्स के सह-संस्थापक हैं।

क्या है

- इस विशेष सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। फोर्ब्स ने उन्हें सेल्समैन एवं असाधारण रिंगमास्टर कहा है।
- इस सूची में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, वर्जिन समूह के संस्थापक रिचर्ड ब्रॉसनन, बर्कशायर हैथवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वॉरेन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और न्यूज कॉर्पोरेशन के कार्यकारी चेयरमैन रुपर्ट मडोक का नाम भी शामिल है।
- सीएनएन के संस्थापक टेड टर्नर, टॉक शो चलाने वाली ओपरा विन्फ्रे, डेल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक माइकल डेल, पे पल, टेस्ला और स्पेसएक्स के सह-संस्थापक इलोन मस्क, फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी शर्ली सैंडबर्ग, स्टारबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हॉवर्ड स्कलज, फेसबुक के सह-संस्थापक मार्क जकरबर्ग का नाम भी इस सूची में है।

भारतीय रक्षा सिद्धांत

सत्तर साल पहले भारत के मानचित्र पर अंग्रेजों ने एक लकीर खींची और पाकिस्तान का उदय हुआ। पिछले सत्तर साल के इतिहास को देखें तो पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर आज तक भारत के खिलाफ चार सीधी लड़ाई लड़ चुका है और पिछले करीब तीन दशक से छद्म युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये लगता है कि उनके लिए अशिक्षा, बेरोजगारी बड़ी चुनौती नहीं हैं, बल्कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। नवाज शरीफ के उत्तराधिकारी शाहिद खकान अब्बासी ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर दलील दी है। उन्होंने कहा कि भारत के कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के सामने परमाणु हथियारों का कोई विकल्प नहीं था।

क्या है कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत?

1. कोल्ड स्टार्ट एक सैन्य सिद्धांत है, जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर तैयार किया है।
2. कोल्ड स्टार्ट के अनुसार आदेश मिलने के महज 48 घंटों के भीतर हमला शुरू किया जा सकता है। इतने कम समय में हमला करने से भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को आश्चर्यचकित कर देगी।
3. इस पद्धति में भारतीय सेना के अलग-अलग हिस्सों को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। इस तरह का अभियान पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में होगा।
4. कोल्ड स्टार्ट का सिद्धांत पाक द्वारा परमाणु हमले को रोकना है। इस योजना का मुख्य मकसद शत्रु देश पर जोरदार ढंग से हमला करना है। इसमें बख्तरबंद वाहन और तोपखाना पाकिस्तान के इलाकों में कम से कम समय में प्रवेश कराना है।
5. कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं को कुछ हफ्तों तक एक स्थान पर केवल कुछ दिनों तक तैनाती के लिए बनाया गया था। इसका परीक्षण अभी युद्ध में किया जाना बाकी है। इसका उद्देश्य तत्काल लामबंदी और त्वरित हमले से पाकिस्तान आश्चर्यचकित रह जाएगा।
6. इससे पाकिस्तानी प्रतिक्रिया से पहले ही भारत अपने मकसद को हासिल कर सकेगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा युद्ध रोकने से पहले ही भारत अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकेगा।

बेअसर साबित हो रही हैं पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं

पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणुओं पर बेअसर साबित हो रही हैं। वहीं प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर चुके इन जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए नए एंटीबायोटिक दवाएं नहीं विकसित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में असरदार एंटीबायोटिक का संकट पैदा हो गया है। इस बारे में डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ पैदा हो रही प्रतिरोधक क्षमता के कारण आने वाले वक्त में मौतों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से विश्व में सात लाख मौतें हर साल होती हैं, जो बढ़कर 2050 तक एक करोड़ सालाना हो सकती है। भारत के बारे में अलग से आंकड़ा नहीं है। लेकिन जिन देशों में एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, उनमें भारत भी प्रमुख रूप से शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है। विश्व को इससे निपटने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनानी होगी।

क्या है

1. मौजूदा समय में 22 समूहों की करीब 118 एंटीबायोटिक दवाएं प्रचलन में हैं। इनमें से 24 दवाओं के खिलाफ जीवाणुओं ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली हैं और अब ये बेअसर साबित हो रही हैं। उदाहरण के लिए टाइफाइड में इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक फ्लॉक्ससिन करीब-करीब बेअसर हो चुकी। डब्ल्यूएचओ ने ऐसे 12 जीवाणुओं की सूची जारी की है, जिन पर कोई एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं।
2. डब्ल्यूएचओ ने पुरानी दवाओं के बेअसर होने पर चिंता जताई है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता इस बात पर जताई है कि नई एंटीबायोटिक दवाएं कम बन रही हैं।
3. अभी दुनिया में कुल 51 एंटीबायोटिक दवाओं पर काम चल रहा है। लेकिन डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इनमें से आठ ही नई हैं। बाकी पुरानी दवाओं को सुधार कर बनाई जा रही हैं। इसलिए इन आठ दवाओं

पर ही उम्मीद टिकी है। लेकिन डब्ल्यूएचओ का मानना है कि यह कम है क्योंकि बेकार हो रही दवाओं की संख्या तीन गुनी है।

4. एंटीबायोटिक के बेअसर होने के तीन प्रमुख कारण हैं। एक, कम या ज्यादा इस्तेमाल करना, दूसरे एक से अधिक एंटीबायोटिक्स साथ लेना, तीसरे, जरूरत नहीं होने के बावजूद इस्तेमाल करना।

दुनिया की सबसे अमीर महिला का हुआ निधन

दुनिया की सबसे अमीर बिजनेसवुमेन में से एक लिलियानी बितनकोह का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। बितनकोह के परिवार ने ही फेमस कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की स्थापना की थी। बितनकोह की बेटी ने उनके निधन की न्यूज की पुष्टि की। बितनकोह ने बीती रात अपने घर में ही आखिरी सांस ली। लिलियानी एक समय दुनिया की सबसे अमीर महिला रह चुकी थीं।

क्या है

1. इस साल 2017 में लिलियानी बितनकोह की कुल संपत्ति 40 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने वर्ष 2012 में कंपनी का बोर्ड छोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें सार्वजनिक तौर पर कम ही देखा गया लेकिन वह उम्र बढ़ने की वजह से भूलने की बीमारी का पता चलने के बाद शोषण मामले के कारण वे सुर्खियों में रहीं।
2. फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक लिलियानी सौंदर्य प्रसाधन कंपनी लॉरियल में अभी भी प्रमुख शेयरधारक थीं और दुनिया की 14वीं सबसे अमीर हस्ती थीं।
3. कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जीन पॉल एगॉन ने कहा, शहम लिलियानी बितनकोह को हमेशा सराहते रहे हैं।
4. वह हमेशा ही लॉरियल, कंपनी और इसके कर्मचारियों से जुड़ी रहीं। 'उन्होंने कहा, लिलियानी बितनकोह का कंपनी की सफलता में योगदान रहा है। सौंदर्य से परिपूर्ण महिला हमें छोड़कर चली गई और हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।'

मटीरीअल रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव ऐसे पहले एशियाई बन गए हैं जिन्हें मटीरीअल रिसर्च के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'वोन हिप्पल अवार्ड' के लिए चुना गया है। यह अवार्ड अमेरिका स्थित मटीरीअल रिसर्च सोसायटी (एमआरएस) का सर्वोच्च सम्मान है।

क्या है

1. प्रशस्ति पत्र में नैनोमटीरीअलस, ग्राफीन, 2डी मटीरीअलस, सुपरकंडक्टिविटी और कोलोसल मैग्नेटोरेसिस्टेंट पर राव के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया गया है।
2. जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राव को यह अवार्ड 29 नवंबर को बोस्टन में एमआरएस की बैठक के दौरान प्रदान किया जाएगा।
3. भारत रत्न सीएनआर राव इस सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस अवार्ड में नकद राशि, ट्राफी और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

बार वीवीपीएट मशीन का उपयोग

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति अगले माह गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा के लिए गांधीनगर आएंगे। देश में पहली बार इस विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपीएट मशीन लगेगी तथा मतदाताओं को बूथ के नक्शे के साथ मतदाता पर्ची दी जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या करीब दो हजार से बढ़ाकर 50 हजार 120 कर दी है। आयोग इस चुनाव में करीब 75 हजार ईवीएम मशीन का उपयोग करेगा, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से भी मंगा ली गई है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ईवीएम के साथ वीवीपीएट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन लगाना पड़ेगा। इसके लिए आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक ने दस हजार जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 5 हजार वीवीपीएट मशीन उपलब्ध करा दी हैं जबकि 60 हजार मशीनों की और जरूरत है।

क्या है

1. गौरतलब है कि गुजरात की पाटीदार नेता रेशमा पटेल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर ईवीएम के साथ वीवीपीएट लगाकर ही चुनाव कराने की मांग की थी।
2. रेशमा ने देश के विविध राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद गुजरात चुनाव में सत्ताधारी दल की ओर से गड़बड़ी की आशंका जताते हुए यह याचिका दाखिल की थी।
3. देश में पहली बार गुजरात चुनाव में वीवीपीएट मशीन का उपयोग होगा।
4. राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी बीबी स्वेन ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्योति से मुलाकात के बाद राज्य सरकार को आगामी 10 अक्टूबर तक आवश्यक प्रशासनिक फेरबदल करने को कहा है।
5. अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ गुजरात आएंगे। संभवत इस दौर में राज्य चुनाव की तिथि भी घोषित हो सकती है।

राजीव महर्षि बने नए कैंग

पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि अब देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 62 वर्षीय महर्षि ने शशिकान्त शर्मा की जगह ली है। शर्मा ने 23 मई, 2013 को कैंग का पद संभाला था। शपथ ग्रहण समारोह में उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।

क्या है

1. राजस्थान कैडर के 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी महर्षि ने पिछले महीने गृह सचिव के रूप में 2 साल का तय कार्यकाल पूरा किया था।
2. कैंग के रूप में महर्षि का कार्यकाल तीन साल का होगा। कैंग की नियुक्ति छह साल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की जाती है।
3. संवैधानिक अधिकारी के तौर पर कैंग के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों के ऑडिट की जिम्मेदारी होती है। कैंग की रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश की जाती है।
4. महर्षि राज्य और केंद्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गृह सचिव के पद पर नियुक्ति से पूर्व वह आर्थिक मामलों के सचिव और राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं।
5. इसके अलावा वह रसायन और उर्वरक विभाग तथा विदेश मामलों के विभाग में सचिव पद पर सेवाएं भी दे चुके हैं।

55 फीसद आउटसोर्सिंग पर भारतीय का कब्जा

वर्तमान में भारतीय आइटी कंपनियां 80 देशों के 200 शहरों में कारोबार कर रही हैं। कुल आउटसोर्सिंग के 55 फीसद पर इन्हीं भारतीय कंपनियों का कब्जा है। उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की मजबूत स्थिति को रेखांकित करते हुए केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही। वह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कैपिटल फाउंडेशन सोसायटी की ओर से 'उभरती डिजिटल दुनिया में भारत' विषय पर आयोजित वार्षिक व्याख्यान व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मौजूद थे।

क्या है

1. इस कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद को न्यायमूर्ति पीएन भगवती राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2. यशोदा फाउंडेशन के एमडी डॉ. प्रेम नारायण अरोड़ा को कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति प्रो. तलत अहमद व जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. भरत एच देसाई को प्रो. टी शिवाजी राव पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आइटी सेक्टर में वर्तमान में 30 लाख लोग काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में एक तिहाई महिलाएं कार्यरत हैं। अगले चरण में अमेजन, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी आइटी कंपनियां भारत आने की तैयारी कर रही हैं।
3. भारत में मोबाइल क्रांति का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ दिन पूर्व देश में एक भी कंपनी मोबाइल नहीं बनाती थी।

4. अब देशभर में 95 मोबाइल कंपनियों ने अपने प्लांट स्थापित कर दिए हैं। इनमें से 32 नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं।

प्लैट्स रैंकिंग 2017

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है। प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी की रैंकिंग के अनुसार आरआईएल पांच पायदान उछलकर तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर रूस की गैस कंपनी **Gazprom** और दूसरे पर जर्मनी की ई.ऑन कंपनी है।

क्या है

1. सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) वर्ष 2017 में सातवें स्थान पर आ गई है। बीते वर्ष 2016 में कंपनी की रैंकिंग 14 थी।
2. आईओसी की रैंकिंग में तेज उछाल देखने को मिला है। वर्ष 2015 में कंपनी की रैंकिंग 66 थी। वहीं, वर्ष 2017 में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) की रैंकिंग 11वीं रही है, जो कि बीते वर्ष 20वें पायदान पर थी।
3. प्लैट्स ने अपने एक बयान में कहा है कि एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग में इस बार कुल 14 भारतीय एनर्जी कंपनियों ने इस सूची में जगह बनाई है, जो कि बीते वर्ष कि तुलना में एक कम है।
4. दुनिया की सबसे बड़ी रिफायनरी कॉम्पेक्स की मालिक रिलायंस बीते वर्ष 7वें स्थान पर रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा कोल उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड बीते वर्ष की 38वीं पोजिशन से खिसकर 45वें स्थान पर आ गया है।
5. इस सूची में अन्य भारतीय कंपनियों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (39वें), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (48वें), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन (81वें) और गेल इंडिया लिमिटेड (106वें) स्थान पर हैं।
6. रूस की Gazprom इस बार लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है। इस कंपनी ने अमेरिकी ऑयल एंड गैस कंपनी एक्सॉनमोबिल की जगह ली है, जो कि पिछले 12 वर्षों से पहले स्थान पर कायम रही थी। इस बार यह टॉप 10 में 9वें स्थान पर रही है।

दुनिया में बेजोड़ है मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा

छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (सीएसआइए) की सीआइएसएफ सुरक्षा को विश्व में सबसे अच्छी सुरक्षा मानी गई है। सीएसआइए की सीआइएसएफ सुरक्षा को ग्लोबल क्वालिटी रेटिंग एजेंसी ने सबसे बेहतर बताया है। सीआइएसएफ अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को हैंड बैगेज की टैगिंग और स्टैपिंग व्यवस्था से राहत देना, यात्रियों की बढ़ती संख्या को सुचारू रूप से संभालना, सीआइएसएफ कर्मियों का शिष्टाचार और उनके मदद के स्वभाव, यात्रियों के भूल गए सामान की रखवाली और यात्रियों द्वारा सीआइएसएफ की मौजूदगी में सुरक्षित होने की भावना को ध्यान में रख कर यह मूल्यांकन किया गया है।

क्या है

1. सीआइएसएफ 21 अगस्त 2002 से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है।
2. छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे व्यस्त और अतिसंवेदनशील हवाई अड्डा है।
3. यहां की सुरक्षा में वर्तमान में 5000 सीआइएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं।
4. इस एयरपोर्ट से लगभग 4.1 करोड़ यात्रियों ने 2015-16 के दौरान सुरक्षित रूप से यात्रा की है।

कांडला पोर्ट का नाम बदला

जहाजरानी मंत्रालय ने कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर (25 सितंबर, 2017 से लागू) दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट करने से संबंधित आदेश जारी किया है। कच्छ के रण में स्थित कांडला पोर्ट ट्रस्ट देश के 12 सबसे बड़े

बंदरगाहों में से एक है। मंत्रालय के आदेशानुसार, केंद्रीय सरकार ने भारतीय पोर्ट अधिनियम, 1908 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के आधार पर कांडला का नाम संशोधित कर दीन दयाल किया है।

क्या है

1. कांडला बंदरगाह पर विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मई महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह सुझाव दिया था कि कांडला पोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट कर देना चाहिए।
2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय समाज के गरीब और कमजोर तबकों के विकास के लिए समर्पित रहे।
3. सालभर तक चलने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्मशती समारोह के समापन के अवसर पर जहाजराणी मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया।

साल 2017 की हरुन रिच लिस्ट

योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालाकृष्ण और डी-मार्ट के राधाकिशन दमानी ने मुकेश अंबानी के साथ साल 2017 की हरुन रिच लिस्ट में स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट में लगातार छठे साल मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। शेयर बाजार में आये उछाल से रिलायंस के शेयर्स में बढ़त देखने को मिली और इस वजह से अंबानी की संपत्ति 58 फीसद बढ़कर 2570 अरब रुपये के स्तर पर पहुंच गई। उनकी यह संपत्ति यमन देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से 50 फीसद अधिक है। वैश्विक स्तर पर वो वह पहली बार शीर्ष 15 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।

क्या है

1. हरुन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “बालकृष्ण जो कि पतंजलि के सीईओ हैं और योगगुरु बाबा रामदेव के बचपन के मित्र हैं, अब देश के टॉप 10 अमीरों में शामिल हो गए हैं।
2. वहीं रिटेल सेक्टर के नए सितारे दमानी सबसे लंबी छलांग लगाने वाले अमीर रहे। उनकी संपत्ति में 320 फीसद का इजाफा हुआ है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की शानदार सूचीबद्धता से अमीरों की सूची में आठ नये लोगों को जगह मिली है।”
3. बालकृष्ण पिछले साल 25 वें स्थान पर थे लेकिन वो इस साल आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी संपत्ति में 173 फीसद का इजाफा देखने को मिला और वह बढ़कर 70,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। पतंजलि का वित्त वर्ष 2017 में कुल टर्नओवर 10,561 करोड़ रुपये रहा था और उन्होंने बड़े बड़े ब्रैंड को अच्छी खासी टक्कर दी थी।

शक्तिशाली महिला उद्यमियों की सूची में भारतीय

अमेरिका से बाहर की सबसे शक्तिशाली महिला उद्यमियों की फोर्ब्स सूची में दो भारतीयों को शामिल किया गया है। इनमें आइसीआइसीआइ बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर का नाम भी शामिल है। सूची में इन्हें पांचवें पायदान पर रखा गया है। वहीं दूसरी भारतीय महिला शिखा शर्मा रही है। यह एक्सिस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। सूची में इन्हें 21वां स्थान मिला है। इस सूची में स्पेन की बांको सैंटेंडर समूह की कार्यकारी अध्यक्ष अना बोटिन शीर्ष स्थान पर रही हैं।

क्या है

1. चंदा कोचर आइसीआइसीआइ बैंक का बीते आठ वर्षों से नेतृत्व कर रही हैं। सात सितंबर, 2017 को समाप्त हुए 12 महीनों में बैंक की मार्केट कैप 20.2 फीसद बढ़कर 30 बिलियन डॉलर हो गई है।
2. वर्ष 2016 में कंपनी का राजस्व 9.1 फीसद बढ़ा है। देश में बीते वर्ष नोटबंदी की घोषणा के बाद से बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए रिटेलर्स और छोटे व्यवसायों के साथ साझेदारी की थी।
3. वहीं शिखा शर्मा के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन उन्हें तीन वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक के तिमाही नतीजों में लगातार नुकसान दर्ज करने के चलते इसके बेचे जाने के कयास लगाए जा रहे थे। इसे खरीदने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक ने रुचि दिखाई थी।

4. शर्मा बैंक की डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। इसमें वह बैंक डिजिटल पेमेंट एप की पहुंच को भी बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। इस वर्ष जुलाई में शर्मा ने घोषणा की थी कि एक्सिस बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनी फ्रीचार्ज का अधिग्रहण कर लिया है।

बिटक्वाइन को टक्कर देगा जे क्वाइन

जल्द ही जापान के बैंक अपनी क्रिप्टोकॉरेसी बाजार में उतारने वाले हैं। इस क्वाइन का नाम जे-क्वाइन हो सकता है। जापान के बैंक जल्द ही जापान की जनता को कैशलेस होने की सुविधा देने जा रहे हैं। मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप वह पहला संस्थान है जो इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है। अन्य संस्थानों के साथ अध्ययन बैठकों का दौर जारी है। इस प्रोजेक्ट में बैंकों का संघ भी शामिल है जिसमें बैंक ऑफ जापान भी है। उम्मीद की जा रही है कि यह जे-क्वाइन 2020 टोक्यो ओलंपिक के समय जारी हो सकता है।

क्या है

1. मिजुहो बैंक ने भागीदार संस्थानों और जे-क्वाइन लांच करने की इस प्रोजेक्ट को रेगुलेटर की इजाजत नहीं मिली है। जापानी मुद्रा येन के सामने इसे उतारा जाएगा और उम्मीद है कि मोबाइल एप पर यह डिजिटल करेंसी काम करेगी।
2. मिजुहो पिछले कई महीनों से डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है। वह ब्लॉकचेन तकनीक पर भी काम कर रहा है जो क्रिप्टोकॉरेसी के लिए जरूरी है।
3. इस साल की शुरुआत में बैंक जापान से ऑस्ट्रेलिया अपनी एक ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से खास डाक्यूमेंट को भेजने का काम पूरा करके देख चुका है।
4. गौरतलब है कि जापान ने इस साल की शुरुआत में बिटक्वाइन को मंजूरी दे दी थी और बड़े रिटेलर इसे स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी जापान में काफी बड़ी संख्या में लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं।
5. सरकार इसे रोकने के लिए जे-क्वाइन की मदद लेने के मूड में दिख रही है।

BSF के 'ऑपरेशन अर्जुन'

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सीमा के करीब स्थित पाकिस्तानी सेना के वर्तमान और पूर्व सैन्य अफसरों के घरों और खेतों पर निशाना लगाकर हमला कर रही है, जिससे पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का अनुरोध करने को मजबूर हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तानी स्नाइपर्स द्वारा भारतीय सैनिकों को मारने और सीमावर्ती गांवों और ग्रामीणों पर गोलीबारी के बाद 'ऑपरेशन अर्जुन' नाम से अभियान शुरू किया है। भारत के इस अभियान के बाद पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गयी है और शांति चाहती है। इसलिए उन्होंने संघर्ष विराम का अनुरोध किया है।

क्या है

1. पाकिस्तान ने सेना के अपने रिटायर हो चुके अफसरों को सीमा के नजदीक जमीनें दी है ताकि वो वहां से घुसपैठ कराने में अपने अनुभव से मदद कर सकें और भारती विरोध अभियानों के संचालन में मदद दे सकें।
2. ऑपरेशन अर्जुन के तहत भारतीय सेना ने रिटायर हो चुके इन पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और पाकिस्तानी रेंजर्स के घरों और खेतों को निशाना बनाया, जो घुसपैठ और भारत विरोधी अभियान में मदद कर रहे थे।
3. बीएसएफ की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स पंजाब के डीजी मेजर जनरल अजगर नवीद हयात खान ने बीएसएफ के डायरेक्टर केके शर्मा को पिछले हफ्ते में दो बार फोन किया और गोलीबारी रुकवाने का अनुरोध किया। रिपोर्ट के अनुसार शर्मा ने पाकिस्तानी डीजी हयात खान को पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी पर कड़ा एतराज जताया। बगैर किसी उकसावे के पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गयी गोलीबारी में भारतीय आम नागरिकों के जानो माल का नुकसान होता रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी डीजी ने बीएसएफ के डायरेक्टर शर्मा को पहली बार 22 सितंबर को फोन किया था और फिर दोबारा सोमवार (25 सितंबर) को भी कॉल की।
4. यह अभियान पिछले साल तीन महीने तक चले 'ऑपरेशन रुस्तम' की तर्ज पर था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक सेना की गोलाबारी का जवाब देने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था।

वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट 2018 में भारत

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने भारत में शिक्षा के स्तर की पोल खोलकर रख दी है। इसमें कहा गया है कि भारत उन 12 देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है जहां दूसरी कक्षा के छात्र एक छोटे से पाठ का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते। सूची में मलावी पहले स्थान पर है। भारत समेत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपने अध्ययन के नतीजों का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने कहा कि बिना ज्ञान के शिक्षा देना न केवल विकास के अवसर को बर्बाद करना है बल्कि दुनियाभर में बच्चों और युवाओं के साथ बड़ा अन्याय भी है।

क्या है

1. विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वैश्विक शिक्षा में ज्ञान के संकट की चेतावनी दी। कहा, 'इन देशों में लाखों युवा छात्र बाद के जीवन में कम अवसर और कम वेतन की आशंका का सामना करते हैं क्योंकि उनके प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए शिक्षा देने में विफल हो रहे हैं।'
2. वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट 2018: लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस में कहा गया, श्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के तीन चौथाई छात्र दो अंकों के घटाने वाले सवाल हल नहीं कर सकते और पांचवीं कक्षा के आधे छात्र ऐसा नहीं कर सकते।
3. शिक्षा बिना ज्ञान के गरीबी मिटाने और सभी के लिए अवसर पैदा करने और समृद्धि लाने के अपने वादे को पूरा करने में विफल होगी। यहां तक कि स्कूल में कई वर्ष बाद भी लाखों बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते या गणित का आसान-सा सवाल हल नहीं कर पाते।
4. इसमें कहा गया है कि ज्ञान का यह संकट सामाजिक खाई को छोटा करने के बजाय उसे और गहरा बना रहा है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा, 'ज्ञान का यह संकट नैतिक और आर्थिक संकट है। जब शिक्षा अच्छी तरह दी जाती है तो यह युवाओं से रोजगार, बेहतर आय, अच्छे स्वास्थ्य और बिना गरीबी के जीवन का वादा करती है। समुदायों के लिए शिक्षा खोज के लिए प्रेरित करती है, संस्थानों को मजबूत करती है और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाती है।' उन्होंने कहा कि ये फायदे शिक्षा पर निर्भर करते हैं और बिना ज्ञान के शिक्षा देना अवसर को बर्बाद करना है।
5. विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 में ग्रामीण भारत में पांचवीं कक्षा के केवल आधे छात्र ही दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर की किताब अच्छे से पढ़ पा रहे थे, जिसमें उनकी स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले बेहद सरल वाक्य शामिल थे। इस रिपोर्ट में ज्ञान के गंभीर संकट को हल करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने की सिफारिश की गई है।

नेशनल टूरिज्म अवार्ड

पर्यटन के विकास में बेहतर काम करने के लिए गुजरात को नेशनल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य के पर्यटन मंत्री गनपत सिंह व प्रधान सचिव एसजे हैदर को हाल ऑफ फेम श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केरल, गोवा, राजस्थान व आंध्रप्रदेश को भी सम्मानित किया गया।

क्या है

1. हाल ऑफ फेम को इस बार शामिल किया गया है। यह उन्हें दिया जाएगा जो राज्य, संस्था और एजेंसी तीन साल तक एक श्रेणी में लगातार तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतेंगे।

महिला गाइड सम्मानित

1. राष्ट्रपति ने 91 वर्षीय रमा खांडवाला को स्पेशल बेस्ट टूरिस्ट गाइड अवार्ड से नवाजा।
2. आजाद हिंद फौज के झंडे तले आजादी की लड़ाई लड़ने वाली रमा मानती हैं कि उम्र उनके इरादों को नहीं रोक सकती।
3. मुंबई निवासी बुजुर्ग महिला ने समारोह में बताया कि उन्हें स्लम में रहना पड़े तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां लोग बुजुर्गों की ख्याल रखते हैं।
4. जापानी भाषा बोलने में महारथ रखने वाली रमा ने इस दौरान अपने संस्मरण मौजूद लोगों को बताया।

2. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गुजरात ने पर्यटन के मोर्चे पर बेहतरीन काम किया है। बाकी के राज्यों को उससे सबक लेने की जरूरत है। उनका कहना था कि पर्यटन उद्योग तेजी से अपने पैर पसार रहा है।
3. 1950 में जहां 2.5 करोड़ पर्यटक सारे विश्व में थे, वहीं 2016 में इनकी तादाद 123 करोड़ तक पहुंच गई है। कोविंद ने मंत्रालय से कहा कि वह इस तरह की नीति बनाए जिससे पर्यटन की लागत में तो कमी हो, लेकिन पर्यटक को मिलने वाले लाभ ज्यादा हो सकें। उन्होंने इस दौरान मंत्रालय के तीन कार्यक्रमों को लांच किया। कोविंद का कहना था कि पर्यटन उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन का काम भी करता है। गरीबी को खत्म करने का काम इसके जरिये किया जा सकता है।

एनडीएमए के 13वें स्थापना दिवस

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरण रिजिजू ने किसी आपदा के दौरान त्वरित एवं प्रभावी प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रथम उत्तरदाता की क्षमता को मजबूत बनाने की जरूरत रेखांकित की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के 13वें स्थापना दिवस, जिसकी थीम विद्यालय सुरक्षा थी, के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री किरण रिजिजू ने कहा कि आपदा जोखिम में कमी लाने (डीआरआर) की शिक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि आपदा की तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

क्या है

1. पिछले वर्ष आपदा जोखिम में कमी पर एशियाई मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा आपदा जोखिम कमी (डीआरआर) के लिए दस सूत्रीय एजेंडा का जिक्र करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार एक सुरक्षित, मजबूत और गतिशील भारत के विजन के प्रति वचनबद्ध है।
2. इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि भारत एक आपदा संवेदनशील देश है और आपदाओं का सामना करना अपरिहार्य है, श्री रिजिजू ने कहा कि डीआरआर में सकारात्मक परिणाम केवल राज्य सरकारों, जिला एवं स्थानीय प्रशासन तथा समुदाय आधारित संगठनों की भागीदारी के साथ ही अर्जित किए जा सकते हैं।
3. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरआर) ने देश भर के स्कूलों में भूकंप की तैयारी करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए हैं एवं सैकड़ों छात्रों को संवेदनशील बनाया गया है।

विदेशियों की नजर में बेहतर हुआ भारत

विदेशियों के रहने और काम करने के लिहाज से भारत की रैंकिंग में जबर्दस्त उछाल आया है। इस मामले में ग्लोबल रैंकिंग में भारत 14वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले भारत की स्थिति में 12 स्थान का उछाल आया है। एचएसबीसी के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। इस साल मार्च और अप्रैल के दौरान 159 देशों के 27,587 लोगों पर यह सर्वेक्षण किया गया। इसमें सिंगापुर प्रवासियों की पहली पसंद रहा।

क्या है

1. एचएसबीसी के मुताबिक अर्थव्यवस्था, अनुभव और पारिवारिक मानकों के संयुक्त पैमाने पर इस साल भारत 12 पायदान ऊपर आया है।
2. भारत में बहुत से विदेश से प्रवासी काम और वित्तीय अवसर की तलाश में आते हैं, लेकिन अब यहां आने वाले अपने परिवार के लिए भी इसे बेहतर जगह मान रहे हैं।
3. पेशेवर तरक्की के मामले में भारत प्रवासियों की पसंद के टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। करियर में निखार के लिहाज से भारत को बेहतर बताने वाले प्रवासियों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 12 फीसद की वृद्धि हुई है।
4. करीब 63 फीसद प्रवासियों ने इस मामले में भारत को अच्छा देश बताया है। इस श्रेणी में भारत की रैंकिंग सातवीं है। सर्वे में 71 फीसद विदेशी प्रवासियों ने यहां की अर्थव्यवस्था में भरोसा जताया।
5. राजनीतिक स्थिरता को लेकर 58 फीसद प्रवासी आशावादी दिखे। 50 फीसद से ज्यादा प्रवासियों ने व्यापार शुरू करने की दृष्टि से अच्छा देश बताया।

- परिवार के साथ बसने के मामले में भारत प्रवासियों की दूसरी पसंद बन गया है। ज्यादातर का मानना है कि यहां उनकी पारिवारिक जिंदगी अच्छी हुई है। 48 फीसद विदेशियों का मानना है कि यहां बच्चे आसानी से दोस्त बना लेते हैं। इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।

भारत के आईएमआर में उल्लेखनीय कमी

भारत में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। हाल ही में जारी एसआरएस बुलेटिन के मुताबिक, वर्ष 2016 में भारत के आईएमआर में तीन अंकों (8 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2015 में जन्मे 1000 बच्चों में से 37 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। यह आंकड़ा वर्ष 2016 में घटकर 34 के स्तर पर आ गया है। इससे पिछले वर्ष भारत के आईएमआर में दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, भारत में जन्मे कुल बच्चों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है, जो पहली बार घटकर 25 मिलियन के स्तर से नीचे आई है। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 के दौरान भारत में 90,000 कम नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। वर्ष 2015 में 9.3 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2016 में 8.4 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई थी।

क्या है

- एसआरएस बुलेटिन के मुताबिक नवजात बच्चे एवं बच्चियों की संख्या में अंतर निरंतर घटता जा रहा है। नवजात बच्चियों एवं बच्चों की मृत्यु दर में अंतर घटकर अब 10 फीसदी से भी कम रह गया है। इससे सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना को काफी बढ़ावा मिला है।
- उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि मंत्रालय की रणनीतिक अवधारणा के सकारात्मक नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही इस मामले में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास भी अब सार्थक साबित हो रहे हैं। जहां तक सशक्त क्रियाशील समूह (ईएजी) वाले राज्यों का सवाल है, उत्तराखंड को छोड़ सभी राज्यों के आईएमआर में वर्ष 2015 की तुलना में कमी दर्ज की गई है।
- यह कमी बिहार में 4 अंकों, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में 3-3 अंकों और छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं राजस्थान में 2-2 अंकों की रही है।
- सरकार की विभिन्न पहलों के जरिये स्वास्थ्य सेवा कवरेज बढ़ाने के देशव्यापी प्रयासों के परिणामस्वरूप भी सिर्फ एक साल में ही ये उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
- सेवा प्रदान करने की व्यवस्था को मजबूत करना, गुणवत्ता का आश्वासन, आरएमएनसीएच+ए, मानव संसाधन एवं समुदाय संबंधी प्रक्रियाएं, सूचना एवं ज्ञान, दवाओं एवं निदान और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इत्यादि भी इनमें शामिल हैं।

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई के तीन नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। खातों में न्यूनतम राशि की कमी और खाता बंद करवाने के लिए सर्शत शुल्क हटाने से लोगों को थोड़ी राहत होगी। वहीं ट्राई के इंटरकनेक्शन चार्ज कम करने से फोन करना सस्ता हो सकता है।

एसबीआई के नए नियम

- खाते में न्यूनतम राशि की सीमा घटी: बैंक के मुताबिक अब महानगरों में बैंक खाते में न्यूनतम राशि रखने की सीमा 5000 से घटाकर 3000 रुपये कर दी जाएगी।
- अकाउंट बंद करना निशुल्क: नए महीने से बैंक खाता बंद करवाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, शर्त यह होगी कि खाता खुलने के 14 दिन के भीतर या एक साल बाद खाता बंद किया जाए। 14 दिन के बाद और एक साल से कम दिनों में खाता बंद करवाने पर 500 रुपये शुल्क और जीएसटी लगेगा।
- अलग नहीं होंगे चेक: स्टेट बैंक में अन्य सहयोगी बैंकों का विलय हो गया है। लेकिन अब तक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, पटियाला, मैसूर, हैदराबाद, बीकानेर और जयपुर के ग्राहक संबंधित बैंकों का ही चेकबुक इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 1 अक्टूबर से ये चेक अमान्य हो जाएंगे और ग्राहकों को एसबीआई का चेक बुक लेना होगा।

टेलीफोन सेवा

1. ट्राई के आदेश के पर 1 अक्टूबर से इंटरकनेक्शन चार्ज 14 पैसे प्रति कॉल से घटकर छह पैसे रह जाएगा।
2. यह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए कंपनियों को देना होता है।
3. इससे कॉल दरों के और सस्ते होने का रास्ता साफ होगा क्योंकि फायदा ग्राहकों को देना होगा।

क्रिकेट

1. फुटबॉल की तरह अब मैदान में अभद्रता करने वाले क्रिकेटर को अंपायर रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर सकता है।
2. बैट के मानक तय किए गए अब इसकी चौड़ाई 108 मिमी, मोटाई 67 मिमी और कोनों पर 40 मिमी से ज्यादा नहीं होगी।
3. बॉलिंग करने की तैयारी के दौरान क्रीज से बाहर होने वाले बैट्समैन को आउट किया जा सकेगा।

रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर बंट गई विश्व की महाशक्तियां

म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से संयुक्त राष्ट्र की बैठक तो हुई लेकिन महाशक्तियां बंटी नजर आईं। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र की पहली ओपन बैठक में चीन और रूस ने जहां म्यांमार सरकार का समर्थन किया वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चल रही हिंसा रोकने की मांग की। म्यांमार के रोहिंग्या संकट ने विकराल रूप ले लिया है। म्यांमार में हिंसा और हत्या से बचने के लिए 25 अगस्त तक पलायन करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने म्यांमार में जारी हिंसा के माहौल को खत्म करने के लिए सुरक्षा परिषद से सख्त कदम उठाने की अपील की है।

क्या है

1. सुरक्षा परिषद की ओपन बैठक में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने म्यांमार की हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने म्यांमार को बर्मा पुकारते हुए काउंसिल सदस्यों से कहा कि हमें इस बात को कहने से नहीं हिचकना चाहिए कि बर्मा अल्पसंख्यक समुदाय के खात्मे के लिए क्रूर कैंपेन चला रहा है। उन्होंने अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसारत होने का आरोप लगाते हुए म्यांमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
2. हेली ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे म्यांमार की सेना को हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दें। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ परिषद के काफी सदस्यों ने हिंसा पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा परिषद की कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया। 88 सिविल सोसायटी और मानवाधिकार संगठनों के वैश्विक गठबंधन ने सुरक्षा परिषद से म्यांमार पर दबाव बनाने की अपील की है।
3. सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों में तीन जहां म्यांमार के खिलाफ खड़े हुए वहीं चीन और रूस ने अलग रुख अपनाया। दोनों ही महाशक्तियों ने रोहिंग्या संकट से जूझने के लिए म्यांमार के कदमों का समर्थन किया। म्यांमार के साथ करीबी संबंध वाले चीन के डेप्युटी यूपन एंबेसडर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार सरकार की चुनौतियों और कठिनाइयों को भी समझना चाहिए।
4. चीनी दूत ने कहा कि म्यांमार को मदद की जरूरत है। उन्हें रखाइन प्रांत में जारी हिंसा को लंबे समय से चली आ रही समस्या बताते हुए कहा कि इसका कोई त्वरित निदान नहीं है।
5. संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने भी चेतावते हुए कहा कि म्यांमार की सरकार पर 'अत्यधिक दबाव' केवल उस देश और आसपास की स्थिति को बिगाड़ेगा ही।

इस कवच को नहीं भेद पाएगी कोई भी गोली

मोर्चे पर डटे जांबाज सैनिकों को अब दुश्मन की गोली की चिंता नहीं रहेगी। अभी तक उपलब्ध बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट भारतीय सैनिकों को पूर्ण सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। साथ ही ये कम सुविधाजनक और बहुत वजनी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी भारतीय सैनिकों को नायाब तोहफा देने जा रहा है। स्वदेश निर्मित

हल्का और अभेद्य रक्षा कवच जांबाजों को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। जिस विशेष पदार्थ से इसे बनाया जाना है, वह सभी परीक्षणों में खरा उतरा है।

क्या है

1. आइआइटी ने 12 माह के प्रयास के बाद एक बेहद हल्का और पूरी तरह अभेद्य कंपोजिट पदार्थ तैयार किया है। इससे बनने वाले बॉडी आर्मर को किसी भी प्रकार की बंदूक की गोली भेद नहीं पाएगी।
2. यह कंपोजिट पदार्थ भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में हर कसौटी पर खरा उतरा है। अब इससे जल्द ही बॉडी आर्मर तैयार किए जाएंगे। डीआरडीओ ने आइआइटी मंडी को यह प्रोजेक्ट सौंपा है।
3. आइआइटी मंडी के सहायक प्रोफेसर डॉ. मुहम्मद तलहा ने बताया कि मैटीरियल इंजाद कर लेने के बाद अब बॉडी आर्मर तैयार करने पर कार्य शुरू हो गया है। इसे सैनिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया है। यह छाती, सिर व पेट को पूरी तरह से कवर करेगा। शरीर के इन्हीं हिस्सों में गोली लगने से जान जाने का सबसे बड़ा खतरा रहता है।
4. कारगिल संघर्ष में सेना मैडल से नवाजे गए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर कहते हैं कि सैन्य, अर्धसैनिक बलों के पास जो बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट हैं, वे बहुत वजनी हैं। उन्हें हर समय पहने रहना संभव नहीं है। पेट की सुरक्षा के लिए अब तक कोई कवच नहीं बन सका है। हालांकि पिछले कुछ साल में हल्के जैकेट और हेलमेट भी आए हैं, लेकिन पेट को कवर करने वाले जैकेट नहीं बने हैं।
5. नक्सल व आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आतंकवादी हमेशा छिप कर वार करते हैं। इससे कई बार जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। कई बार दूर से स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह कवच जवानों के लिए बड़े काम का साबित होगा।

ये है खूबी

1. जिस पदार्थ से यह कवच बनाया जाना है, प्रायोगिक परीक्षण में वह पूरी तरह खरा उतरा
2. इस पदार्थ से बनने वाला बॉडी आर्मर होगा बेहद हल्का और पूरी तरह अभेद्य
3. यह पेट को भी कवर करेगा, जो बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं कर पाती थी
4. यह बॉडी आर्मर हल्का और अभेद्य होगा। यह छाती, सिर व पेट को पूरी तरह से कवर करेगा।